International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628
Received: 16-01-2026, Accepted: 17-02-2026, Published: 06-03-2026
Volume 8, Issue 1, 2026, Page No. 156-157

# भारत अमेरिका व्यापार संबंधः एवं वर्तमान विश्व व्यवस्था में ट्रेड वार भारत के परिपेक्ष्य में

**नीतिका**
शोधार्थी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

**सारांश**
वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में व्यापार युद्ध हो या फिर सैनिक युद्ध दोनों ही को कम करने के लिए हर एक देश को आर्थिक संतुलन और आर्थिक मोर्चों पर विवादों को कम से कम करने पर ध्यान देना होगा इसलिए ट्रेड वॉर को लम्बा करने की जगह जल्द से जल्द आर्थिक द्वंद्वो को कम करते हुए ट्रेड डीलों पर सहमति बना लेनी चाहिए जिसका जीता जागता उदा० भारत है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक मतभेदों पर काम किया गया है जिससे विश्व आर्थिक व्यवस्था सुद्रण हो सके। ट्रेड डील मात्र आर्थिक लेन–देन का माध्यम नहीं है अपितु यह भू–राजनीतिक शक्ति एवं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन हैं। वर्तमान में ट्रेड डील केवल व्यापारिक/आर्थिक समझौता नहीं है बल्की यह आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार है वैश्वीकरण वाली इस विश्व व्यवस्था में ट्रेड डीलों का महत्व व्यापक होता जा रहा है जैसे– सप्लाई चेन की सुरक्षा, टैरिफ युद्ध से बचाव और बाजार तक पहुंच, सेवाओं एवं पेशेवरों की एक देश से दूसरे देश तक आवाजाही, रणनीतिक स्वायत्तता, डिजिटल इकॉनमी, टाडा सुरक्षा एवं ग्रीन इकॉनमी के मानक तय करना इत्यादी। 21वीं सदी के तीसरे दशक में ट्रेड डील का मतलब केवल मुनाफा, कमाना नही है अपितु वैश्विक व्यापार को सुलभ, सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाना आर्थिक वस्तुओं की पहुंच को विश्व के हर एक कोने तक पहुंचाना एवं वैश्वीकरण को मजबूत करना भी है।

**मुख्य शब्दः** आर्थिक एकाधिकार, ट्रेड वॉर, प्रशासन, क्रूड ऑयल, व्यापार समझौता, वैश्वीकरण, ब्लड मील, सब्सिडी, संरक्षण

वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में नये आयाम आये है क्योंकि वर्तमान समय में भारत का प्रभाव बड़ा है ऐसे में भारत को नजर अन्दाज करना अब अमेरिका के लिए हितकर नहीं होगा, उसी के परिपेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 'व्यापार समझौता सम्बन्धि सहमती' हुयी इस प्रकार की ट्रेड वार्ताओं ने ट्रेड वॉर को वर्तमान दशक के निम्नत्तम स्तर पर पहुंचा दिया है।

भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर ने दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है इस ट्रेड वॉर की बजह से दोनों देशों के सेन्सेक्स ने बहुत ही गिरावट देखी है जो वर्तमान व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है आज का दौर अधिक से अधिक विकास करने का है, वर्तमान की विदेश नीतियों में विचारधाराओं का अन्त हो गया है और सभी देश केवल और केवल अपने निजी हितों को प्राथमिकता देने में ही अपनी भलाई देख रहें है चाहे फिर वह रूस–युक्रेन वॉर हो, इजराईल – हमास या फिर वेनेजुएला की सम्प्रभुता पर अमेरिका का हमला सभी मसलो पर सारी की सारी विश्व बिरादरी – चुप रही और अपने हितों को ही महत्व देती रही ऐसे में अर्थव्यवस्थाओं पर चोट लगना दोनों ही मुल्कों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या थी जिसपर दोंनों देशों के हित में है। वक्त रहते समझौता हो जाना दोनों ही देशों के हित में हैं। टैरिफ वॉर/ ट्रेड वॉर की शुरुआत को हम ट्रम्प प्रशासन से देखते है यह ट्रम्प 2.0 का नया प्रयोग नहीं था अपितू ट्रम्प 1.0 में भी भारत के साथ व्यापार को मुश्किल करने वाले नियम–कानून बनाये जाने लगे थे जैसे मार्च 2018 में अमेरिका ने भारत से आने वाले स्टील पर 25% का और एल्युमीनियम पर 10% का टेरिफ या आयात शुल्क लगा दिया और कारण बताया की यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार जून 2019 में अमेरिका द्वारा भारत को GSP (Generalized System of Preference) से बाहर कर दिया GSP से भारतीय समानों पर जीरो– ड्यूटी लगती थी, इससे बाहर होने से भारत के मध्यम उद्योगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा विशेषकर टेक्सटाइल उद्योग को, इन सारी अमेरिकी कार्यवाहियों से तंग आकर भारतीय व्यापारियों के विरोध को देखते हुये भारत सरकार द्वारा जवाबी कार्यवाही कि गयी जिसमें अमेरिका से आने वाले 28 उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा भारी टैरिफ लगाया गया

- इसमें बादाम और अखरोट पर टैरिफ बहुत ही बड़ा दिया गया था (जबकि USA बादाम का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है)
- सेब और दालों पर भी आयात शुल्क बड़ा दिया, सेब पर तो शुल्क को 70% तक कर दिया गया था।

चार वर्षों के 'वाइडन प्रशासन' में ट्रेड या टैरिफ को लेकर कोई बड़े बदलाव नहीं किये गये ना ही व्यापक स्तर पर टैरिफ को कमाया गया और ना ही बड़ाया गया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में 'रिपब्लीकन' की जीत हुयी और फिर से मिस्टर ट्रम्प देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना पहले वाला राग अलापना फिर से शुरू कर दिया और फिर से शुरू हुआ ट्रेड वॉर इसकी शुरुआत हम 2025 के मध्य से देखते है जब जगह–जगह ट्रम्प के द्वारा कहा गया की भारत रूस से खनिज तेल ले रहा है जिससे रूस को फंडिंग हो रही है और रूस अभी तक युद्ध में अच्छी स्थिति में है। अमेरिका भारत पर टैक्स लगायेगा अगर भारत रूस से खनिज तेल खरीदना बन्द नहीं कर देता है। इसी क्रम में अगस्त 2025 से ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और कहा गया कि यह अतिरिक्त शुल्क नई दिल्ली द्वारा रुस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल के लिए दंड के रूप में है। यह आयात शुल्क वॉर (टैरिफ वॉर) लगातार नये नये विवादों के साथ बड़ता रहा जिससे एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि लगने लगा था कि दोनों देशों के सम्बन्ध फिर से अच्छे नहीं होगें, दोनों देश एक बड़े आर्थिक विवादों को जन्म देंगे जिससे दोनों देशों की आम जनता को बहुत महगांयी का समना करना पड़ सकता था यह प्रक्रिया ट्रंप प्रशासन की हटधर्मिता को प्रदर्शित कर रही थी।

## अमेरिकी आर्थिक एकाधिकार पर भारत सरकार का रुख

वर्तमान भारत सरकार का रूख हर क्षेत्रों में Defensive के साथ offensive हो गया है। भारत खुद को अमेरिका पर निर्भर नहीं बना रहा है इसलिए भारत द्वारा अपने प्रतिद्वन्दी देश चीन के

साथ भी कई आर्थिक समझौते किये गये जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था किसी एक देश के चंगुल में ना फसे। वर्तमान भारत सरकार का रुख भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने का है इसलिए 'मेक इन इण्डिया' को अधिक महत्व दिया जा रहा है, भारत ने दुनिया को यह बताने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं कि की हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने देश का विकास करना है। भारत दुनिया के किसी भी देश के सामने झुकने को तैयार नहीं होगा चाहे फिर वह विश्व की सबसे बड़ीं अर्थव्यवस्था अमेरिका ही क्योंना हो भारत अपनी शर्तों पर ही कार्य करेगा, भारत ऐसी किसी भी शर्त को मानने के लिए कभी भी सहमत नहीं होगा जो हमारे आर्थिक हितों के विरोधाभासी है जैसे– रूस से कच्चे तेल का व्यापार हो या फिर अमेरिका से अधिक वस्तुओं की खरीदि की बात हो भारत ने अपना रुख साफ कर दीया है कि भारत केवल और केवल उसी डील पर सहमति देगा जो भारतीय हितों की पूर्ति करती हो।

### भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का महत्व

ऊपर वर्णित बातों को देखते हुये अभी हाली में भारत ने यूरोपीय यूनियन (EU) से ट्रेड डील की जो EU के सभी देशों और भारत के आर्थिक हितों की पूर्ति करती है साथ ही साथ EU की अमेरिका पर निर्भरता को कम करती है, जानकारों द्वारा इस डील का इतना प्रभाव बताया गया की इसको "Mother of All Deals" कहा गया है। EU की ट्रेड डील भारत के सामने अमेरिका का एक अच्छा विकल्प के रूप में आयी क्योंकि यूरोपीय यूनियन को विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखते है इसके पास बड़े–बड़े बाजार है जहां पर भारत के सस्ते एवं उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की अच्छी खासी मांग है जिससे हमारे घरेलू बाजार को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावनायें बताई जा रही है। इसी के साथ जो भी वर्तमान में व्यापार समझौते हो रहे है उन सभी में एक कॉमन बात यह भी रखी जा रही है कि भारत के कामगार वर्ग के लिए इन देशों में वीजा के नियमों में आसानी कि जाये जिससे भारतीय लोगों को इन देशों में आसानी से काम मिल सके क्योंकि हम देखते है कि यूरोप के अधिकत्तर देशों में जनसंख्या का इस्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है जिससे वहां पर काम करने योग जनसंख्या बहुत ही कम है इन देशों को स्कील्ड एवं चीप लेबर की बहुत जरूरत है जिसकी पूर्ती भारत से अच्छा और कोई देश नहीं कर सकता है इस व्यापार समझौते से दोनों देशों का भला होगा।

### भारत अमेरिका ट्रेड डील के सामने आने वाली प्रमुख समस्यायें

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते वर्तमान में बहुत कुछ सुधार पर है। लेकिन उनको औपचारिक रूप से क्रियान्वित करने में बहुत कठिनाईयां भी है।

हाल ही में (फरवरी 2025) भारत–अमेरिका के बीच हुऐ समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने में बहुत सी सामस्यायें भी है जैसे– कृषि और डेयरी क्षेत्र, यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच विवाद के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, अमेरिका की मांग है कि भारत अपना कृषि एवं डेयरी बाजार अमेरिका के लिए खोल दे, सेब, अखरोट एवं बादाम पर से आयात शुल्क हटा दे और अमेरिकी, दूध एवं दुग्ध उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचने पर सहमति दे लेकिन भारत की चिन्तायें है। कि अगर भारत इस क्षेत्र को अमेरिकी व्यापारियों को खोल देगा तो भारत के किसान एवं लघु उद्यमियों को बहुत नुकसान झलेना पड़ेगा जिससे भारतीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की मांग कम हो सकती है। दुग्ध उत्पादों के सामने सबसे बड़ी समस्या ब्लड मील की है अमेरिका में गायों को मांसाहारी आहार दिया जाता है जबकि हमारे देश में गायें घास फूस खाती है एवं दूध शाकाहारी उत्पादन समझा जाता है जिससे इस प्रकार के दूध का भारतीय बाजार आने से हमारी सांस्कृतिक मान्यताकों पर अघात पहुंचेगा एवं भारतीय दुग्ध उत्पादक किसानों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि अमेरिकी सब्सिडी आधारित दुग्ध उत्पादक वस्तुएं भारतीय बाजार में दुग्ध उत्पादक वस्तुओं की उप्लब्धता को बढ़ा देगी।

अमेरिका की एक मांग है Reciprocal Tariffs जिसमें अमेरिका चाहता है। कि जितना टैक्स भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगायेगा अमेरिका भी उतना ही टैक्स भारतीय उत्पादों पर लगायेगा इस प्रकार की टैरिफ व्यवस्था से भारत को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड सकता है।

### Digital Privacy & Data

भारत सरकार की मांग है कि भारत का डेटा भारत मैं ही सुरक्षित रखा जाये इसके लिए भारत सरकार द्वारा DPDP Act 2023 (Digital Personal Data Protection,SS Act) बनाया है। जिसमें प्रावधान है कि डिजिटल डाटा का संरक्षण देश के अन्दर किया जाये जबकि मेटा गूगल, आदि कम्पनिया इस एक्ट से बहुत ही नाखुश है वह "फ्री फ्लो" की मांग करती हैं।

इन सब बाधाओं के अलावा सबसे बड़ी समस्या वीजा नियनों को मुश्किल करने की है क्योंकि अधिकतर भारतीयों की पसन्द अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करना और फिर वहीं पर रोजगार को अर्जित करना होता है और ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा नियम को बहुत कठिन किया जा रहा है जो भारतीयों के हितों पर आघात करने जैसा है इस प्रकार के कई मुद्दे है जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बहुत ही मुश्किल प्रतीत होती है फिर भी इस इन्तरिम समझौता से सम्भावनाएं बड़ी है सकारात्मक सम्वन्धों की राहे आशान हुई है।

### सन्दर्भ


1. PIB (Press Information Bureau), India
2. दैनिक जागरण, सामाचार पत्र
3. Ministry of external affairs, you Tube channel
4. ORF (Observer Research Foundation), India
5. AIR, News
6. Sansad T.V.